IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विकसित भारत 2047 में हाई स्कूल के विद्यार्थीयों के व्यक्तित्व विकास का योगदान

लेखक: रिसर्च स्कॉलर, श्री सुशील कुमार

सहायक शिक्षक (PGT) USS बेलवारा (सहरसा) बिहार सरकार (BPSC)

सारांश

विकसित भारत 2047 सरकार का विज़न है कि 2047 तक देश को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध अर्थव्यवस्था में बदला जाए। आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नयन, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और स्थिरता इस कार्यक्रम के मानदंड हैं। इसे हासिल करने की दिशा में कदम केंद्रीय बजट 2025-26 में तय किए गए थे, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में बताई गई समग्र रणनीति के अनुसार अवसर पैदा करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्राथमिकताओं की घोषणा की थी। विकसित भारत सिर्फ एक विज़न से कहीं ज़्यादा है; यह 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखने का एक सामूहिक सपना है। यह एक ऐसा भविष्य बनाने पर केंद्रित है जहाँ हर नागरिक, चाहे वह किसान हो, युवा छात्र हो, महिला हो, या हाशिए पर पड़े समुदाय का कोई व्यक्ति हो, उसे विकास और अवसर का वास्तविक मौका मिले। यह यात्रा समाज के हर कोने को छूती है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से लेकर स्मार्ट बुनियादी ढांचे, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा तक। इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम उच्च शिक्षा की फिर से कल्पना कैसे करते हैं। सीखने को अधिक व्यावहारिक, डिजिटल, समावेशी और आज की दुनिया के अनुरूप बनाकर, हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो न केवल नौकरी के लिए तैयार हो, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो। अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्वविद्यालयों, उद्योगों और सरकार के बीच पुल बनाना महत्वपूर्ण होगा। सहयोग, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता के माध्यम से, विकसित भारत हम सभी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, अधिक समान भारत को आकार देने का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 उन महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करती है जो भारत की प्रगति में बाधा डालती हैं, शिक्षा प्रणाली के भीतर वित्तीय बाधाओं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे को प्राथमिक बाधाओं के रूप में पहचानती है। इसके अलावा, NEP 2020 सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6% तक शैक्षिक व्यय बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए रणनीतिक योजना और निष्पादन की आवश्यकता है। इस पेपर का उद्देश्य विकसित भारत@2047 के शैक्षिक क्षेत्र में की गई पहलों और सामने आई चुनौतियों का पता लगाना है, जो वर्तमान शैक्षिक ढांचे में व्यापक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। इन मुद्दों से निपटकर और इनोवेटिव तरीके अपनाकर, भारत शिक्षा की बदलाव लाने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके अपने विकास और समृद्धि को आगे बढ़ा सकता है। कीवर्ड: सस्टेनेबल, इनोवेशन, एम्पावरमेंट, डिजिटल, महत्वपूर्ण।

1. परिचय

किसी भी देश की प्रगति की नींव उसकी शिक्षा प्रणाली होती है। हमें विश्वास है कि शिक्षा, जो किसी भी देश के विकास की आधारशिला है, इस प्रयास के लिए निश्चित रूप से ज़रूरी होगी। भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करने की ज़रूरत है जो सभी भारतीयों को आज़ादी का एहसास कराए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे, और उन्हें इक्कीसवीं सदी के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे। यह पता लगाने के लिए कि शिक्षा का हर पहलू 2047 तक एक जीवंत और सशक्त भारत बनाने में कैसे भूमिका निभाता है, इसके सभी घटकों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए।

1.1 व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास:

(i) कार्यबल को कुशल बनाना: विकसित भारत का लक्ष्य औद्योगिक मांगों और नई तकनीकी प्रगति को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ मिलाना है। हमें उद्यमिता, हरित ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और कृषि सहित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करने चाहिए। विकसित भारत को अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम पेश करने चाहिए ताकि लोग वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त कर सकें।

(ii) मान्यता और प्रमाणन: व्यावसायिक क्षमताओं की मान्यता और रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए, विकसित भारत मज़बूत क्रेडेंशियल तंत्र स्थापित करेगा। व्यावसायिक शिक्षा एक वांछनीय और विश्वसनीय पेशेवर मार्ग बन जाएगी। इसके परिणामस्वरूप लोगों को कौशल हासिल करने और औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार योग्य या स्वरोज़गार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(iii) आजीवन सीखना: ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, माइक्रो-क्रेडेंशियल और व्यावसायिक अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमें निरंतर कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। संस्थानों को वैकल्पिक करियर की तलाश करने वालों या बदलते रोज़गार बाज़ारों के अनुकूल होने वालों की सहायता करनी चाहिए।

(iv) कौशल अंतर को पाटना: विकसित भारत को अपने आर्थिक विस्तार का समर्थन करने के लिए एक प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होगी। इसके लिए कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

(v) उद्यमिता और नवाचार: हर कोई इस बात से सहमत होगा कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्यमिता की शिक्षा को शामिल करना चाहिए, छात्रों के व्यवसायों के लिए इनक्यूबेशन सेंटर प्रदान करने चाहिए, और रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।

1.2 प्रौद्योगिकी का एकीकरण:

(i) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए, विकसित भारत को सभी को सस्ते इंटरनेट, गैजेट्स और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। विश्वसनीय इंटरनेट एक्सेस में महत्वपूर्ण निवेश करें, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

(ii) टेक-सक्षम शिक्षा: प्रौद्योगिकी में शिक्षा को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। एक विकसित भारत में पहुंच में सुधार, निर्देश को अनुकूलित करने और आकर्षक शैक्षिक सामग्री बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। इसमें गेमिफाइड लर्निंग मॉड्यूल, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन और AI-संचालित प्रशिक्षक शामिल हो सकते हैं। एक विकसित भारत में जुड़ाव में सुधार, निर्देश को अनुकूलित करने और पारंपरिक कक्षा सेटिंग्स के बाहर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। बेहतर समझ के लिए, एक विकसित भारत इंटरैक्टिव टूल, सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी अनुभवों का उपयोग करेगा।

(iii) डिजिटल साक्षरता और समावेशन: सभी छात्रों को प्रौद्योगिकी-संवर्धित शिक्षा तक समान पहुंच मिल सके, इसके लिए डिजिटल डिवाइड को खत्म करना होगा। डिजिटल साक्षरता पहलों को प्राथमिकता देना, उचित मूल्य पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना, और सार्वभौमिक रूप से सुलभ शिक्षण वातावरण बनाना, ये सभी एक विकसित भारत का हिस्सा हैं।

(iv) प्रौद्योगिकी का जिम्मेदार उपयोग: प्रौद्योगिकी को अपनाने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। एक विकसित भारत प्रौद्योगिकी शिक्षा में नैतिक मुद्दों पर बहुत जोर देगा, उचित इंटरनेट आचरण और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा।

(v) शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता: एक विकसित भारत में शिक्षकों को कक्षा में प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए निर्देशात्मक दृष्टिकोण और डिजिटल साक्षरता क्षमताओं से लैस किया जाएगा। शिक्षकों के बीच, हमें आजीवन विकास और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

औपचारिक या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अलावा, हमें विकसित भारत के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं को भी हासिल करने की आवश्यकता है।

2. अध्ययन का उद्देश्य

(i) हाई स्कूल के छात्रों के विकास के लिए सरकारी नीति और कार्यक्रम का पता लगाना। (ii) शिक्षा प्रणाली पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण करना।
(iii) भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना।

3. अध्ययन का दायरा और कार्यप्रणाली

(i) मैंने इस शोध में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन कार्यप्रणाली अपनाई है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कार्यप्रणाली में डेटा सबसे पहले अनुभवी व्यक्तियों से और दूसरी बार साहित्य की समीक्षा से इकट्ठा किया गया है। (ii) डेटा संग्रह के तरीकों में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीकों से डेटा इकट्ठा किया गया है।

4. परिणाम और चर्चा

भारत ने परिवर्तनकारी नीतियां अपनाई हैं - पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, और 1991 के आर्थिक उदारीकरण से लेकर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, NEP 2020, और आत्मनिर्भर भारत जैसी हाल की पहलों तक। इन उपायों ने भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर किया है।

क्र. सं.	स्वतंत्रता के बाद के उपाय/कदम	वर्ष	प्रभाव
1	पहली पंचवर्षीय योजना	1951	कृषि, बुनियादी ढांचे और मूल्य स्थिरता में संतुलित विकास को लक्षित किया।
2	दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956	औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।
3	बीस सूत्री कार्यक्रम	1975	भूमि सुधारों और शिक्षा के माध्यम से गरीबी और जीवन की गुणवत्ता को संबोधित किया।
4	सर्व शिक्षा अभियान	2000	प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता को सार्वभौमिक बनाया।
5	डिजिटल इंडिया मिशन	2015	डिजिटल बुनियादी ढांचे और साक्षरता को आगे बढ़ाया।
6	नई शिक्षा नीति (NEP)	2020	व्यावसायिक और डिजिटल फोकस के साथ शिक्षा में सुधार किया।
7	आत्मनिर्भर भारत अभियान	2020	स्थानीय उत्पादन और कम आयात के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।

4.1. भारत में उच्च शिक्षा में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्वालिटी में सुधार और पहुंच की चुनौतियों का एक इनोवेटिव समाधान बनकर उभरी है। शिक्षा में PPP मॉडल में सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेशन या नॉन-प्रॉफिट संगठनों के बीच सहयोग शामिल होता है, ताकि दोनों सेक्टर की ताकतों को मिलाकर आपसी फायदे और सामाजिक विकास किया जा सके।

उच्च शिक्षा में PPP के मुख्य क्षेत्र:

(i) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: भारत में उच्च शिक्षा के तेजी से विस्तार के कारण आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ी है, जिसे सरकारी संस्थान सीमित फंडिंग के कारण पूरा करने में अक्सर संघर्ष करते हैं। PPP के माध्यम से, प्राइवेट कंपनियाँ यूनिवर्सिटी कैंपस, रिसर्च सेंटर और हॉस्टल और लाइब्रेरी जैसी छात्र सुविधाओं के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन में निवेश करती हैं। यह पार्टनरशिप यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी संस्थान एकेडमिक क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जबकि प्राइवेट संस्थाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल लागतों का प्रबंधन करें। (ii) क्वालिटी में सुधार: प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इंडस्ट्री-आधारित करिकुलम और बेहतरीन तरीकों को पेश करके शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाती है। प्राइवेट पार्टनर इंडस्ट्री से जुड़े प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए विशेष विशेषज्ञता लाते हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को जॉब मार्केट द्वारा मांगे जाने वाले कौशल से लैस किया जाए। इसके अलावा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्नत शिक्षण उपकरण और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट निवेश से शिक्षण परिणामों में सुधार हो सकता है। (iii) रिसर्च और इनोवेशन: PPPs रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ अक्सर रिसर्च पहलों में निवेश करती हैं, जिससे यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग मिलती है और उन्हें असल दुनिया की समस्याओं को हल करने का मौका मिलता है। बदले में, यूनिवर्सिटीज़ मूल्यवान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देती हैं, जिसे आपसी फायदे के लिए कमर्शियलाइज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन हब और स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर में सहयोग इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे PPPs अत्याधुनिक रिसर्च को बढ़ावा देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को बढ़ावा देते हैं।
(iv) स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार: सरकार और प्राइवेट सेक्टर का सहयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थान स्किल्स-आधारित लर्निंग पर ध्यान दें। प्राइवेट कंपनियाँ अक्सर छात्रों के लिए इंटर्नशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग और नौकरी के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे एकेडमिक शिक्षा और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच का अंतर कम होता है। इससे न केवल रोज़गार बढ़ता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि छात्रों को थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी मिले।
(v) पहुँच और सामर्थ्य: PPPs समाज के वंचित वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ स्कॉलरशिप, लोन प्रोग्राम या फीस में कमी कर सकती हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, प्राइवेट संस्थान सरकार के साथ मिलकर अधिक किफायती, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

संभावित फायदों के बावजूद, उच्च शिक्षा में PPPs को समान पहुँच सुनिश्चित करने, गुणवत्ता नियंत्रण और प्राइवेट सेक्टर के लाभ-संचालित उद्देश्यों और सार्वजनिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन पार्टनरशिप में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत नियामक ढाँचे की आवश्यकता है। हालाँकि, उचित निगरानी के साथ, PPPs में इनोवेशन को बढ़ावा देकर भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की अपार क्षमता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, और शिक्षा को ज़्यादा सुलभ और इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रासंगिक बनाना।

4.2 उच्च शिक्षा में फैकल्टी विकास और अकादमिक नेतृत्व

2047 तक, एक विकसित भारत में, फैकल्टी विकास और अकादमिक नेतृत्व उच्च शिक्षा की सफलता के लिए केंद्रीय होंगे। विश्वविद्यालय बदलते शिक्षण तरीकों, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए शिक्षकों के लगातार अपस्किलिंग और प्रोफेशनल विकास को प्राथमिकता देंगे। फैकल्टी को ग्लोबल अकादमिक नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कॉन्फ्रेंस और रिसर्च एक्सचेंज के माध्यम से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। AI-संचालित उपकरण फैकल्टी विकास कार्यक्रमों को पर्सनलाइज़ करने में मदद करेंगे, जो व्यक्तिगत ताकत और सुधार के क्षेत्रों के आधार पर प्रोफेशनल विकास के लिए लक्षित संसाधन प्रदान करेंगे। फैकल्टी सदस्यों को डिजिटल शिक्षा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस में विशेषज्ञता से लैस किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे विविध क्षेत्रों में अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान कर सकें। अकादमिक नेतृत्व फैकल्टी सदस्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, उन्हें संस्थागत नीतियों, रिसर्च प्राथमिकताओं और छात्र जुड़ाव को आकार देने में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक समावेशी, नवीन और सहयोगी अकादमिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2047 तक, भारतीय विश्वविद्यालय एक मजबूत अकादमिक नेतृत्व पाइपलाइन विकसित करेंगे, जहाँ फैकल्टी न केवल शिक्षण में उत्कृष्टता हासिल करेगी, बल्कि अभूतपूर्व रिसर्च का नेतृत्व भी करेगी, सामाजिक परिवर्तन लाएगी और शिक्षा के भविष्य को आकार देगी, जो एक विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

4.3 छात्रों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य

2047 तक, एक विकसित भारत में, छात्रों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य को उच्च शिक्षा के ज़रूरी पहलुओं के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ देंगी, जिसमें कैंपस में आसानी से मिलने वाली काउंसलिंग, पीयर सपोर्ट नेटवर्क और 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। मानसिक स्वास्थ्य सहायता रोज़ाना कैंपस जीवन का हिस्सा होगी, जिसमें प्रशिक्षित पेशेवर और AI-आधारित टूल छात्रों को तनाव, चिंता और पढ़ाई के दबाव को मैनेज करने में मदद करेंगे। भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल होंगे, जैसे योग, फिटनेस और माइंडफुलनेस सेशन, जिनका मकसद लचीलापन और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देना होगा। छात्रों को जीवन भर काम आने वाले मुकाबला करने के कौशल सिखाने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तनाव प्रबंधन पर वर्कशॉप को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ एक समावेशी कैंपस माहौल बनाने पर भी ध्यान देंगी जहाँ अलग-अलग बैकग्राउंड के छात्र, जिनमें हाशिए पर पड़े समूह और विकलांग लोग शामिल हैं, खुद को समर्थित महसूस करें। आराम, आत्म-चिंतन और सामाजिक मेलजोल के लिए सुरक्षित जगहें मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगी, जिससे मदद मांगने के बारे में कलंक कम होगा। 2047 में, भारतीय उच्च शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता के तौर पर अपनाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्र न केवल अकादमिक रूप से सफल हों, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी संतुलित हों, और एक समृद्ध और समावेशी समाज में योगदान देने के लिए तैयार हों।

4.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और उच्च शिक्षा पर इसका प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के लिए लचीलापन, समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख प्रावधान पेश करती है। इनमें कला, विज्ञान और व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करके बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50% तक बढ़ाना शामिल है। HEIs को पाठ्यक्रम डिजाइन, अनुसंधान और शैक्षणिक शासन में अधिक स्वायत्तता दी गई है, जिससे उन्हें नवाचार करने और बदलती जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए सशक्त बनाया गया है। प्रमुख शैक्षणिक सुधारों में पाठ्यक्रम में लचीलापन शामिल है, जिससे छात्रों को व्यक्तिगत सीखने के रास्ते डिजाइन करने और विभिन्न चरणों में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। यह बहु-विषयक सीखने पर जोर देने से पूरक है, जो छात्रों को विविध विषयों

का पता लगाने और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। NEP अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की भी वकालत करती है, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में द्विभाषी शिक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी को बनाए रखती है।

NEP का लक्ष्य शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना है, एक केंद्रीकृत प्रणाली से ऐसी प्रणाली में बदलाव करना है जहां विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का शैक्षणिक निर्णयों पर अधिक नियंत्रण हो। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण (NHERA) जैसे निकायों के निर्माण के साथ, नियामक ढांचे को सरल बनाया गया है, जिससे संस्थानों को अधिक शैक्षणिक स्वतंत्रता मिलती है। यह विकेंद्रीकरण HEIs को क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने और शिक्षा और अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाता है।

भारत सरकार ने विभिन्न शैक्षिक विषयों, योजनाओं, पहलों और नीतियों को लागू किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण, जिसे नारी शक्ति कहा जाता है, देश के बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। हाल के वर्षों में, अलग-अलग समूहों ने महिलाओं को ज़्यादा प्रमुख पदों पर लाने, पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और ज़्यादा समान और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए मिलकर प्रयास किए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ खास पहलों में सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, पीएम कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मातृ वंदना योजना, सर्वदा शक्तिशाली: सशस्त्र बलों में ग्लास सीलिंग तोड़ना, महिला प्रौद्योगिकी पार्क और महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ ही विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शामिल हैं, जो प्रतिभाशाली लड़कियों को STEM के कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत में शिक्षा का क्षेत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लागू होने के साथ एक परिवर्तनकारी दौर से गुज़र रहा है, जो "विकसित भारत@2047" के विज़न के अनुरूप है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के लिए एक मज़बूत नींव रखती है। NEP 2020 में बताए गए रणनीतिक ढांचे में न केवल मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया गया है, बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी आकांक्षाओं को भी व्यक्त किया गया है।

NEP 2020 द्वारा पेश किए गए करिकुलम में व्यापक बदलाव 21वीं सदी के समाज के संदर्भ में फ्लेक्सिबिलिटी, समावेशिता और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा, यह पॉलिसी विभिन्न शैक्षिक फोकस के बीच संतुलन और एकीकरण हासिल करने के महत्व पर ज़ोर देती है, जिससे छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा, जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। शिक्षा के भविष्य पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव को पहचानते हुए, NEP 2020 शैक्षिक ढांचे के भीतर कई डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म को शामिल करने की वकालत करता है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) की स्थापना शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य इनोवेटिव एडटेक समाधानों को बढ़ावा देना है। NEP 2020 के तहत प्रस्तावित तकनीकी प्रगति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अमीर और वंचित समुदायों के बीच मौजूद डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास करती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, यह पॉलिसी महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निरंतर व्यावसायिक विकास और शिक्षक भर्ती बोर्डों के गठन का समर्थन करती है। NEP 2020 शिक्षक क्षमता-निर्माण पहलों में निवेश के माध्यम से पूरे देश में सीखने के परिणामों को बढ़ाने और शिक्षण मानकों को ऊपर उठाने की आकांक्षा रखता है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा अभियान (राष्ट्रीय शिक्षा मिशन), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTA), PM USHA, स्टडी इन इंडिया, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (MUSK), शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम, युवा महत्वाकांक्षी

दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब (SWAYAM), और SWAYAM प्रभा (टीवी कार्यक्रम) जैसे विभिन्न कार्यक्रम इस व्यापक शैक्षिक सुधार रणनीति के अभिन्न अंग हैं।

(i) दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण: दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण समावेशिता और सामाजिक प्रगति का एक मूलभूत तत्व है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार मिलें और वे समुदाय में पूरी तरह से एकीकृत हों। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलें लागू की गई हैं: विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (UDID), ट्रांसजेंडर अधिकारों का समर्थन करने वाला कानून, नायकों की पहचान के माध्यम से जनजातीय गौरव की बहाली, वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, और दिव्यांगजनों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के प्रावधान सहित विकलांगों और बुजुर्गों की सहायता के उद्देश्य से तकनीकी हस्तक्षेप।
(ii) कौशल विकास: कौशल विकास देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति और मानव पूंजी को बढ़ाने में एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हाल के सालों में, वर्कफोर्स की क्षमताओं और अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों के बीच स्किल्स के गैप को पाटने के लिए मिलकर कोशिशें की गई हैं। सरकार ने युवाओं में कौशल हासिल करने को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पहले से सीखे गए कौशल को मान्यता देना, स्किल यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के बीच सहयोग, सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs), और शिक्षा, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के साथ कौशल विकास को जोड़ना शामिल है ताकि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को आसान बनाया जा सके, जिससे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मज़बूत हो। (iii) टेक-इनेबल्ड इंडिया: टेक-इनेबल्ड इंडिया अलग-अलग सेक्टरों में डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति की एक बदलाव लाने वाली कहानी बताता है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने हाल के सालों में काफी ध्यान खींचा है। भारत सरकार ने आधार, डिजि-लॉकर, जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत जैसी कई प्रमुख पहलों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI), समकालीन टेक्नोलॉजी के लिए UNG यूनिफाइड मोबाइल ऐप, स्टेट स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (SSDI), एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान, और स्मार्ट शहरों के लिए जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) के ज़रिए प्रभावी ढंग से लागू किया है।

इसके अलावा, कई अन्य पहल और कार्यक्रम हैं जो भारत में ज्ञान और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं, जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN), ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, फ़्लिप्ड क्लासरूम, ई-पाठशाला, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकली एनहैंस्ड लर्निंग (NPTEL), नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (NMEICT), INFLIBNET का N-लिस्ट प्रोग्राम, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस योजना (शाला अस्मिता), शाला गुणवत्ता (शगुन पोर्टल), राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डी-नोवो संस्थान, और शोध चक्र।

भारत में कम साक्षरता दर की चुनौती देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में एक बड़ी बाधा है, जो गरीबी और असमानता के चक्र को मजबूत करती है। साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों, जैसे सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के बावजूद, कई कारक देश भर में कम साक्षरता स्तर को बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर 77.70% दर्ज की गई, जिसमें पुरुष साक्षरता 84.70% और महिला साक्षरता 70.30% थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (NFHS-5) से पता चलता है कि वयस्क महिलाओं (15-49 वर्ष) के लिए साक्षरता दर 71.5% है, जबकि इसी आयु वर्ग के वयस्क पुरुषों के लिए यह 87.4% है। इसके अलावा, NSO के राज्य-वार आंकड़ों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर 66.2% है, इसके बाद राजस्थान में 69.7% और बिहार में 70.9% है।

पुरुष साक्षरता (2021)	84.70%
महिला साक्षरता (2021)	70.30%

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान: बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) ज़रूरी कौशल हैं जो बच्चे के पूरे जीवन सीखने और विकास का आधार बनते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि जन्म से छह साल तक के साल, जिन्हें बुनियादी साल कहा जाता है, हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस दौरान छूटे हुए मौके वापस नहीं मिल सकते।

हालांकि, भारत में FLN से जुड़ी कई बड़ी रुकावटें हैं जो बच्चों की पढ़ाई में प्रगति और कुल मिलाकर भलाई में बाधा डालती हैं। अलग-अलग सरकारी और गैर-सरकारी सर्वे से पता चलता है कि हम अभी सीखने के संकट का सामना कर रहे हैं: बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल के छात्र–जिनकी संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है–बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल नहीं कर पाए हैं। UNESCO के अनुसार, दस साल के लगभग दो-तिहाई बच्चे एक आसान टेक्स्ट को पढ़ने और समझने में संघर्ष करते हैं। 2023 की वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (ASER) कई चिंताजनक आँकड़ों पर प्रकाश डालती है: - 14-18 साल के लगभग 25% लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में स्टैंडर्ड II के लेवल पर धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते।

5. निष्कर्ष

आजकल करियर डेवलपमेंट सिर्फ़ डिग्री हासिल करने या प्रैक्टिकल अनुभव लेने से कहीं ज़्यादा है, बल्कि इसके लिए दुनिया में कई ज़रूरी गुणों और डायनामिक बदलावों को अपनाने की ज़रूरत है। विकसित भारत: विज़न 2047 तभी हासिल होगा जब हर स्टेकहोल्डर खुद को विज़न 2047 के साथ जोड़ेगा। विकसित भारत को हासिल करने के लिए एक मज़बूत रिसर्च इकोसिस्टम एक ज़रूरी स्तंभ है। R&D में निवेश करके, सहयोग को बढ़ावा देकर, पॉलिसी की रुकावटों को दूर करके, और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत खुद को साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर सकता है। ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल किए बिना एक विकसित भारत की यात्रा अधूरी है, और केवल एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड रिसर्च फ्रेमवर्क के ज़रिए ही देश अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। अब कार्रवाई करने का समय है, और सामूहिक प्रयासों से, भारत एक ज्ञान-आधारित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र में बदल सकता है।

6. संदर्भ

(i) आचार्य, एम. (2024, 7 फरवरी). विकसित भारत 2047: अर्थ, विजन, उद्देश्य, पंजीकरण। क्लियरटैक्स। https://cleartax.in/s/viksit-bharat-2047

(ii) एडमिन। (2024, 26 फरवरी). साक्षरता दर 2024 के अनुसार भारतीय राज्य | भारत में साक्षरता दर 2024। फाइंड ईज़ी। https://www.findeasy.in/indian-states-by-literacy-rate/

(iii) ASER 2023 जिला भागीदार संगठन। (2024). वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER 2023: बियॉन्ड बेसिक्स)। ASER सेंटर। https://doi.org/10.5281/zenodo.5713757.

(iv) “उच्च शिक्षा नीति सुधार: विकसित भारत @2047 की ओर भारत का मार्ग प्रशस्त करना।” (2024). <http://bvicam.in/INDIACom/news/ViksitBharat2024Proceedings/papers/14.pdf>.

(v) शिक्षा मंत्रालय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (PDF) यहाँ उपलब्ध है: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.